(अमन चौधरी, जे.)

अमन चौधरी जे.के समक्ष

तरुण याचिकर्ता

वनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी

2022 का सी. आर. एम.-एम. सं. 37714

25 अगस्त, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 438-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. एस. 342, 365, 395, 412-शस्त्र अधिनियम, 1959-एस. 25-धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व-गिरफ्तारी जमानत देने के लिए याचिका-प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं-याचिकाकर्ता ढाई साल से अधिक समय तक गिरफ्तारी से बचने का प्रबंधन करने से भागने की संभावना दिखाई देती है-याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई भगोड़ा कार्यवाही-जमानत देने पर सह-अभियुक्त के साथ समानता की मांग करना गलत धारणा है क्योंकि सह-अभियुक्त को धारा 439 के तहत मुख्य रूप से हिरासत के आधार पर जमानत दी गई है-याचिका खारिज कर दी गई।

माना जाता है कि घटना के स्थान को राजमार्ग मानते हुए, जिस तरह से पिस्तौल का उपयोग करके अपराध किए गए हैं और उसके बाद, शिकायतकर्ता को आंख बंद करके एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां उसे बंद कर दिया गया और बाद में उसे जान से मारने की धमकी देने के बाद सड़क पर फेंक दिया गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।यह तथ्य कि याचिकाकर्ता जनवरी, 2020 से यानी ढाई साल से अधिक समय से अपनी गिरफ्तारी से बचने का प्रबंधन कर रहा है, यह दर्शाता है कि अग्रिम जमानत देने की संभावना में उसके न्यायाधीश से भागने की पूरी संभावना है।इसके अलावा, जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने कहा है, याचिकाकर्ता के खिलाफ पी. ओ. कार्यवाही शुरू की गई है।सह-अभियुक्त को जमानत देने और उस पर समानता की मांग करने पर याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की निर्भरता गलत धारणा है, क्योंकि सह-अभियुक्त को खंड 439 दंड प्रक्रिया सहिता के तहत जमानत दी गई थी,

(पैरा 7)

मुख्य रूप से हिरासत के आधार पर वर्तमान मामले में गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए आजीवन कारावास या 10 साल के कठोर कारावास की अवधि लगाई जा सकती है।जिस तरह से अपराध

करने का आरोप लगाया गया है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपराध करने वाले अभियुक्त की हिम्मत को दर्शाता है। वर्तमान समय में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं (पैरा 8)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए और जय प्रकाश सिंह (उपरोक्त) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अग्रिम जमानत देने के कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत में रियायत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अफजल हुसैन ने कहा,

गौरव बंसल, ए. ए. जी, हरियाणा।

अमन चौधरी, जे. (मौखिक)

(1) यह भारतीय दंड संहिता की खंड 395,397,342,365,412 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की खंड 25 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15 दिनांक 25.01.2020 के मामले मे पूर्व-गिरफ्तारी जमानत देने के लिए खंड 438 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत दायर दूसरी याचिका है, जो पुलिस स्टेशन मानेसर, जिला गुरुग्राम में दर्ज है।

(2) संलग्नक पी-1 के रूप में इस याचिका से जुड़ी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विचाराधीन घटना एनएच-8 पर केएफसी के सामने एक फ्लाईओवर के पास दिंनाक 22-23.01.2020 की दरम्यानी रात में हुई थी, जब एक सफेद रंग की कार पीछे से आई थी।आरोपी अपनी कार को शिकायतकर्ता के वाहन के सामने ले आए।उक्त कार में 5 से 6 लोग सवार थे।इनमें से तीन व्यक्ति ड्राइवर की ओर से और एक व्यक्ति कंडक्टर की ओर से शिकायतकर्ता के वाहन में सवार हुए।उनमें से एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता की छाती पर पिस्तौल तान कर उसे पीछे की सीट पर धकेल दिया और अन्य लोग उस पर बैठ गए और उसे पीटने लगे और लगभग 7,000 रुपये और मोबाइल फोन छीन लिया। एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का वाहन फ्लाईओवर के आगे सर्विस रोड पर चलाया और उसे पार्क करने के बाद, शिकायतकर्ता की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और दो लोगों ने उसे कार की पिछली सीट पर रख दिया, जिसे एक व्यक्ति चला रहा था और उसके ऊपर बैठ गए और उनमें से एक ने उस पर पिस्तौल तान दी। तीन घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। लगभग 9 बजे, दिंनाक 23.01.2020 को उन्होंने उसकी आँखों पर पट्टी बांध दी और उसे कार में डाल दिया और लगभग 10 बजे, उसे आखिरकार फिरोजपुर झिरका रोड पर छोड़ दिया गया और उन्होंने उसे धमकी दी और उसे अपने गाँव जम्मू जाने के लिए कहा और अगर वह पुलिस के पास जाता है, तो वे उसे गोली मार देंगे।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और उन्हें केवल एक सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के कारण नामित किया गया है और उनसे कुछ भी बरामद नहीं

किया जाना है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि उसके सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जाती है।

(4) राज्य के विद्वान वकील इस आधार पर याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने का जोरदार विरोध करते हैं कि यह एक गंभीर अपराध है और इस मामले मे वसूली की जानी है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध मे दिनांकित 25.1.2020 है और याचिकाकर्ता का नाम इस मामले में 6.2.2020 पर सामने आया जब उसे उसके सह-अभियुक्त द्वारा नामित किया गया था, हालाँकि, तब से, याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच गया है।उन्होंने आगे कहा कि आठ में से पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वर्तमान याचिकाकर्ता सहित शेष अभियुक्तों के खिलाफ भगोड़ा. कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(5) पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ता सुनी।

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय ने जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य 1 मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"6. हमने पक्षों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

7. खंड 438 दंड प्रक्रिया सहिता के प्रावधान अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं, जो निम्नानुसार है: "438. गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश।-
(1) जहाँ किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप अन्य बातों के साथ साथ गिरफ्तार किया जा सकता है, वह इस खंड के तहत निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय अन्य बातों के साथ साथ आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति अन्य बातों के साथ साथ उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा; और वह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारकों को ध्यान अन्य बातों के साथ साथ रखते हुए, अर्थात्:-
(i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(ii) आवेदक की पूर्ववृत्तियां इस तथ्य सहित कि क्या उसने पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कारावास झेला है;

(iii) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना और

(iv) जहां आवेदक को इस तरह से गिरफ्तार करके उसे घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है, या तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दें या अग्रिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश जारी करें।"

1 (2012) 4 एससीसी 379

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की ओर से आरोप की प्रकृति और गंभीरता सहित अग्रिम जमानत देने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

XXX XXX XXX

13. जहां तक मामले के मूल्यांकन का संबंध है कि जमानत दी जानी है या नहीं, धारा 438 और 439 दंड प्रक्रिया सहिता के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।हालांकि, न तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है और न ही नियमित जमानत।अग्रिम जमानत एक असाधारण विशेषाधिकार होने के कारण केवल असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए।अदालत को दिए गए न्यायिक विवेकाधिकार का उचित तरीके से उपयोग यह तय करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या यह अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

XXX XXX XXX

21. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था और चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनायास दर्ज की गई थी, इसलिए इसकी सत्यता विश्वसनीय है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को बहुत हल्के में खारिज कर दिया है कि प्राथमिकी अनायास दर्ज की गई थी और आगे कोई कारण दर्ज नहीं किया कि वैधानिक प्रावधान में शामिल पूर्व-आवश्यकता शर्तें कैसे पूरी हुईं। न ही अदालत ने इस बात पर विचार किया कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है या नहीं।"

(7) प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, यह देखते हुए कि घटना का स्थान राजमार्ग है, जिस तरह से पिस्तौल का उपयोग करके अपराध किए गए हैं और उसके बाद, शिकायतकर्ता की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां उसे बंद कर दिया गया और बाद में उसे जान से मारने की धमकी देने के बाद सड़क पर फेंक दिया गया।यह तथ्य कि याचिकाकर्ता जनवरी, 2020 से यानी ढाई साल से अधिक समय से अपनी गिरफ्तारी से बचने का प्रबंधन कर रहा है, यह दर्शाता है कि अग्रिम जमानत देने की संभावना में उसके न्यायाधीश से भागने की पूरी संभावना है। इसके अलावा, जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने कहा है । याचिकाकर्ता के खिलाफ भगोड़ा करने की कार्यवाही शुरू की गई है। सह-अभियुक्त को जमानत देने और उस पर समानता की मांग करने पर याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की निर्भरता गलत धारणा है, क्योंकि सह-अभियुक्त को मुख्य रूप से हिरासत के आधार पर खंड 439 द.प्र.स. के तहत जमानत दी गई थी।

(8) वर्तमान मामले में गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए आजीवन कारावास या 10 साल के कठोर कारावास की अवधि लगाई जा सकती है।जिस तरह से अपराध करने का आरोप लगाया गया है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपराध करने वाले अभियुक्त की हिम्मत को दर्शाता है।वर्तमान समय में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत हाथ की आवश्यकता है।

(9) अपराध की गंभीरता को देखते हुए और जय प्रकाश सिंह (उपरोक्त) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अग्रिम जमानत देने के कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत में रियायत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

(10) तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

दिव्या गुर्ने

रजनीश सिंगला

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।